



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 234]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अगस्त 20, 2010/श्रावण 29, 1932

No. 234]

NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 20, 2010/SHRAVANA 29, 1932

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरुआत संबंधी अधिमूचना

नई दिल्ली, 20 अगस्त, 2010

विषय : चीन जन. गण., ईयू, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन तथा अमेरिका के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडा ऐश के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच की शुरुआत।

सं. 14/17/2010-डीजीएडी.— यतः मै. अल्कली मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई), जो “सोडा ऐश”, के उत्पादकों की एक एसोसिएशन है, ने 1995 में यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (जिसे एतदपश्चात अधिनियम कहा जाएगा) तथा सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन एवं संग्रहण तथा क्षति निर्धारण हेतु) नियमावली, 1995 (जिन्हें एतदपश्चात नियम कहा जाएगा) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें एतदपश्चात प्राधिकारी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है जिसमें उन्होंने चीन जन. गण., ईयू, केन्या, ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, अमेरिका और यूक्रेन (जिन्हें एतदपश्चात् संबद्ध देश कहा गया है) के मूल के अथवा वहाँ से निर्यातित सोडा ऐश (जिसे एतदपश्चात संबद्ध वस्तु कहा गया है) के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जांच शुरु किए जाने का अनुरोध किया है।

2. और यतः प्राधिकारी ने पाया है कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु के पाटन, घरेलू उद्योग की क्षति तथा पाटन एवं क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं और वे एतद्वारा किसी कथित पाटन की उपस्थिति और मात्रा एवं प्रभाव का निर्धारण करने तथा पाटनरोधी शुल्क की राशि जिसे यदि लागू किया जाए तो वह घरेलू उद्योग की क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी, की सिफारिश करने के लिए उपरोक्त नियमावली के नियम 5 के अनुसार कथित पाटन एवं परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को हुई क्षति की जांच प्रारंभ करते हैं।

### घरेलू उद्योग

3. यह याचिका मै. अल्कली मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एएमएआई) द्वारा दायर की गई है और लागत निर्धारण तथा क्षति संबंधी सूचना मै. जीएचसीएल लि., मै. डीसी डब्ल्यू. मै. निरमा और मै. सौराष्ट्र कैमिकल्स लि. (एससीएल) द्वारा प्रस्तुत की गई है। याचिका में प्रदत्त सूचना के अनुसार अप्रैल, 2009-दिसम्बर, 2009 के दौरान भारत के कुल उत्पादन में भागीदार कंपनियों के उत्पादन का हिस्सा 65.40% बनता है। अतः मौजूदा जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक “घरेलू उद्योग” है।

4. उपर्युक्त की जाँच के पश्चात् प्राधिकारी प्रथम दृष्ट्या यह निर्णय लेते हैं कि याचिकाकर्ता पाटनरोधी नियम के नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है।

### विचाराधीन उत्पाद एवं समान वस्तुएँ

5. वर्तमान याचिका में विचाराधीन उत्पाद डाईसोडियम कार्बोनेट है, जिसे सोडा ऐश के नाम से जाना जाता है और जिसका रासायनिक सूत्र  $\text{Na}_2\text{CO}_3$  है। याचिकाकर्ता ने अनुरोध किया है कि भारतीय उत्पादकों द्वारा सोडा ऐश का उत्पादन दो रूपों में किया जाता है— लाइट सोडा ऐश तथा डेन्स सोडा ऐश। दोनों प्रकारों में अंतर बल्क घनत्व का है। इसके अतिरिक्त सोडा ऐश का उत्पादन कृत्रिम तरीके से और प्राकृतिक तरीके, जिसे विघटन प्रक्रिया कहा जाता है, से किया जा सकता है। वर्तमान याचिका में सोडा ऐश के सभी प्रकार और रूप शामिल हैं।

6. सोडा ऐश डिटर्जेंट, साबुन, क्लीनिंग कम्पाउंड्स, सोडियम आधारित रसायन, फ्लोट ग्लास, कंटेनर और स्पेशियलिटी ग्लास, सिलिकेट तथा अन्य औद्योगिक रसायनों के विनिर्माण में प्रयुक्त होने वाला अनिवार्य घटक है। टेक्सटाइल, कागज, धातुकर्म उद्योगों और विलवणीकरण संयंत्रों में भी इसका व्यापक इस्तेमाल किया जाता है।

7. वर्गीकरण : सोडा ऐश सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 28 के अंतर्गत एक अकार्बनिक रसायन के रूप में वर्गीकृत है। यह उत्पाद आईटीसी (एचएस) कोड 2836.20 के अंतर्गत वर्गीकरणीय है। तथापि यह वर्गीकरण सांकेतिक है और किसी भी प्रकार से वर्तमान जाँच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

8. आवेदक ने दावा किया है कि उनके द्वारा उत्पादित वस्तुएँ संबद्ध देशों के मूल की, अथवा वहाँ से निर्यातित वस्तुओं के “समान वस्तुएँ” हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तुएँ तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से तुलनीय हैं और भौतिक, तकनीकी विनिर्देशनों, प्रकार्यों तथा अंतिम उपयोग के संदर्भ में प्रतिस्थापनीय हैं। अतः जाँच के प्रयोजनार्थ आवेदक द्वारा उत्पादित सोडा ऐश को पाटनरोधी नियम के अर्थ के भीतर संबद्ध देशों से आयातित संबद्ध वस्तु के “समान वस्तु” माना जा रहा है।

## शामिल देश

9. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन. गण., ईयू, केन्या, पाकिस्तान, ईरान, यूक्रेन तथा अमेरिका हैं। चूँकि तुर्की से किए गए आयातों की मात्रा न्यूनतम से कम है अतः तुर्की को वर्तमान जाँच के दायरे से बाहर कर दिया गया है।

## पाटन

### सामान्य मूल्य

#### चीन जन. गण. तथा यूक्रेन के मामले में सामान्य मूल्य

10. याचिकाकर्ता ने चीन जन. गण. तथा यूक्रेन दोनों के लिए गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा किया है और तदनुसार पाटनरोधी नियम के अनुबंध I के पैरा 7 के अनुसार बिक्री, सामान्य एवं प्रशासनिक खर्च एवं लाभ से संबंधित समायोजन सहित भारत में विधिवत समायोजित उत्पादन लागत के आधार पर परिकलित सामान्य मूल्य का निर्धारण किए जाने का दावा किया है।

#### ईयू, अमेरिका, केन्या तथा पाकिस्तान के मामले में सामान्य मूल्य

11. ईयू तथा अमेरिका के संबंध में सामान्य मूल्य प्रथम दृष्ट्या एक अग्रणी अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका "हरीमन केमसल्ट" में उल्लिखित भारित औसत मासिक कीमत पर आधारित है। जहाँ तक केन्या का संबंध है, याचिकाकर्ता द्वारा सामान्य मूल्य का निर्धारण केन्या में टाटा कैमिकल्स की सहायक कंपनी से संबंधित तुलन पत्र में दी गई सूचना के आधार पर किया गया है। पाकिस्तान के संबंध में आईसीआई-पाकिस्तान लि. के तुलन पत्र में उल्लिखित संबद्ध उत्पाद की घरेलू बिक्री कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा किया गया है।

#### ईरान के मामले में सामान्य मूल्य

12. याचिकाकर्ता ने परिकलित मूल्य नीति को ध्यान में रखते हुए ईरान में सामान्य मूल्य का दावा किया है।

13. जाँच शुरुआत के प्रयोजनार्थ प्राधिकारी ने प्रथम दृष्ट्या याचिकाकर्ता के दावे के अनुसार सामान्य मूल्य को ही संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य माना है।

### निर्यात कीमत

14. याचिकाकर्ता ने विचाराधीन उत्पाद की निर्यात कीमत का निर्धारण डीजीसीआई एंड एस के आंकड़ों के आधार पर किया है। कारखाना द्वार स्तर पर निवल निर्यात कीमत का निर्धारण करने के

लिए समुद्री भाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, अंतर्देशीय भाड़ा, पत्तन व्यय और बैंक प्रभार के आधार पर समायोजन किया गया है। याचिकाकर्ता द्वारा निवेदित निवल निर्यात कीमत के संदर्भ में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद है।

### पाटन मार्जिन

15. इस बात के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं कि संबद्ध देशों में संबद्ध वस्तुओं के सामान्य मूल्य निवल निर्यात कीमतों से काफी अधिक हैं जिससे प्रथम दृष्ट्या यह संकेत मिलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा संबद्ध वस्तुओं का पाटन किया जा रहा है। सामान्य मूल्य एवं निर्यात कीमत की तुलना कारखाना द्वार स्तर पर की गई है जिससे संबद्ध देशों के संदर्भ में अत्यधिक पाटन मार्जिन प्रदर्शित होता है।

### क्षति एवं कारणात्मक संबंध

16. याचिकाकर्ता ने वास्तविक क्षति के संबंध में विभिन्न मानदण्डों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है। आवेदक ने इस बात से संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं कि कथित पाटन के परिणामस्वरूप उत्पादन, क्षमता उपयोग, लाभ, निवेश पर आय, नकद प्रवाह और बाजार हिस्से में कमी तथा अत्यधिक कीमत कटौती और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण कम कीमत पर बिक्री के रूप में घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। घरेलू उद्योग को हुई वास्तविक क्षति और संबद्ध देशों से पाटित आयातों के कारण क्षति होने के पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य मौजूद हैं।

### जांच की अवधि

17. आवेदक ने जांच अवधि में अप्रैल, 2009 से दिसम्बर, 2009 (9 माह) की अवधि शामिल किए जाने का प्रस्ताव किया है। इस अवधि को केवल जांच शुरुआत के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि मानते हुए प्राधिकारी ने वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ अप्रैल, 2009 से मार्च, 2010 की अवधि को जांच की अवधि माना है। तथापि क्षति जांच अवधि में अप्रैल, 06-मार्च, 07, अप्रैल, 07-मार्च, 08, अप्रैल, 08-मार्च, 09 और जांच की अवधि शामिल होगी।

### सूचना प्रस्तुत करना

18. भारत में इस जांच से संबंधित समझे जाने वाले निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को निर्धारित प्रपत्र में और ढंग से संगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए अलग से लिखा जा रहा है। वर्तमान जांच में शामिल होने का इच्छुक -कोई अन्य पक्ष भी निम्नलिखित को अपने आवेदन प्रेषित कर सकता है :

निर्दिष्ट प्राधिकारी  
(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)  
भारत सरकार  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय  
वाणिज्य विभाग  
उद्योग भवन, नई दिल्ली-110101

समय सीमा

19. इस जांच से संबंधित कोई भी सूचना लिखित रूप में प्राधिकारी के पास उपर्युक्त पते पर इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 40 दिन के भीतर पहुँच जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा अधूरी सूचना प्राप्त होती है, तो निर्दिष्ट प्राधिकारी, उपर्युक्त नियमावली के अनुसरण में, रिकार्ड में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने परिणाम दर्ज कर सकते हैं।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

20. नियम 6(7) के अनुसार कोई भी हितबद्ध पक्षकार अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के अगोपनीय सारांश वाली उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है।

21. सभी हितबद्ध पक्षकार उपर्युक्त नियम के नियम 7(1) के अनुसार उपलब्ध कराई गई गोपनीय सूचना के लिए नियम 7(2) के अनुसार गोपनीय एवं अगोपनीय सारांश उपलब्ध कराएंगे।

22. ऐसे मामलों में जहाँ हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना देने से इन्कार करते हैं अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डालते हैं तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं और केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

पी. के. चौधरी, निर्दिष्ट प्राधिकारी

3287 97/10-2

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF ANTI-DUMPING AND ALLIED DUTIES)****INITIATION NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th August, 2010

**Subject : Initiation of Anti-dumping Investigation on Imports of Soda Ash originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA.**

**No.14/17/2010-DGAD.**— M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI), an Association of producers of the "Soda Ash" have filed a petition before the Designated Authority (herein after referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended in 1995 and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on dumped articles and for determination of injury) Rules, 1995 (herein after referred to as Rules) for initiation of anti dumping investigation concerning imports of Soda Ash (hereinafter referred to as subject goods) originating in or exported from China PR, EU, Kenya, Iran, Pakistan, Turkey, USA, and Ukraine (hereinafter referred to as subject countries)

2. AND WHEREAS, the Authority finds that sufficient prima facie evidence of dumping of subject goods by the subject countries, injury to the domestic industry and causal links between the dumping and injury exist, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping, and consequential injury to the domestic industry in terms of the Rules 5 of the said Rules, to determine the existence, degree and effect of alleged dumping and to recommend the amount of antidumping duty, which if levied would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

**Domestic Industry**

3. The petition has been filed by M/s Alkali Manufacturers' Association of India (AMAI) and the costing and injury information has been provided by, M/s GHCL Ltd., M/s DCV, M/s Nirma and M/s Saurashtra Chemicals Ltd.(SCL). According to the information provided in the petition, the production of participating companies constitutes 65.40% of Indian production during Apr'09-Dec'09. Thus, the applicant constitutes "domestic industry" for the purpose of the present investigation.

4. The Authority after examining the above, prima facie determines that the petitioner constitutes domestic Industry within the meaning of the rule 2(b) of the AD Rules.

**Product under consideration & Like Articles**

5. The product under consideration in the present petition is Disodium Carbonate, popularly known as Soda Ash with chemical formula  $\text{Na}_2\text{CO}_3$ . The petitioner has stated that the Soda Ash is produced in two forms by the Indian Producers - Light Soda Ash and Dense Soda Ash. The difference in the two types is bulk density. Further, Soda Ash can be produced through synthetic route and natural route, known as dissolution process. The present petition is stated to include all types and forms of Soda Ash.

6. Soda Ash is an essential ingredient in the manufacture of detergents, soaps, cleaning compounds, sodium based chemicals, float glass, container and specialty glasses, silicates and other industrial chemicals. It is also widely used in textiles, paper, metallurgical industries and desalination plants.

7. Classification: Soda Ash is an inorganic chemical classified under Chapter 28 of the Customs Tariff Act. The product is classifiable under ITC (HS) Code 2836.20. The Customs classification is, however, only indicative and in no way binding on the scope of the present investigation.

8. The applicant has claimed that the goods produced by them are "like articles" to the goods originating in or exported from the subject countries. The subject goods produced by the domestic industry and imports from subject countries are comparable, technically and commercially substitutable in terms of physical, technical specifications, functions or end-uses. Therefore, for the purpose of investigation, the Soda Ash produced by the applicant are being treated as like articles of Soda Ash imported from subject countries within the meaning of the Anti Dumping Rules.

**Countries involved**

9. The countries involved in the present investigation are China PR, EU, Kenya, Pakistan, Iran, Ukraine and USA. Since volume of imports from Turkey are below de minimis Turkey is excluded from the purview of the present investigation.

**Dumping****Normal Value****Normal Value in case of China PR and Ukraine**

10. Petitioner has claimed Non-market economy status for both China PR and Ukraine and accordingly claimed the constructed normal value on the basis of cost of production in India duly adjusted including adjustment on selling, general and administrative expenses and profit, in terms of para 7 of Annexure I to the AD rules.

**Normal value in case of EU, USA, Kenya and Pakistan**

11. The Normal Value in respect of EU and USA is prima facie based on weighted average monthly price drawn from Hariman Chemsult, a leading international journal

As regards Kenya, normal value is constructed by the petitioner on the basis of information drawn from the Balance Sheet of Tata Chemicals in respect of its subsidiary company in Kenya. In respect of Pakistan, the normal value has been claimed on the basis of domestic selling price of the subject product drawn from the Balance Sheet of ICI Pakistan Ltd.

#### Normal value in case of Iran

12. The petitioner has claimed normal value in Iran considering constructed value approach.

13. For the purpose of initiation, the Authority has prima-facie considered the normal value of subject goods in subject countries as claimed by the petitioner.

#### Export Price

14. The applicants have claimed export price for product under consideration based on the DGCI&S data. Adjustments have been claimed on account of ocean freight, marine insurance, commission, inland freight, port expenses, and bank charges to arrive at net export price at ex-factory level. There is sufficient prima facie evidence with regard to the net export price claimed by the petitioners.

#### Dumping Margin

15. There is sufficient evidence that the normal values of the subject goods in the subject countries are significantly higher than the net export prices indicating prima-facie that the subject goods are being dumped by the exporters from the subject countries. Normal value and export price have been compared at ex-factory level which shows significant dumping margin in respect of subject countries.

#### Injury and Causal Link

16. The petitioner has furnished information on various parameters relating to material injury. The applicant has furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping in the form of fall in production, capacity utilization, profits, return on investments, cash flow, and market share and significant price undercutting and price underselling on account of dumped imports from subject countries. There is sufficient prima-facie evidence of the material injury being suffered by the domestic industry and the same being caused by dumped imports from subject countries.

#### Period of Investigation

17. The applicant has proposed April'09 to Dec'09 (Nine months) as period of investigation. While adopting this period as POI only for the purpose of initiation, the Authority has considered April'09 to March'10 as the POI for the purpose of present investigation. The injury investigation period will however cover the periods April, 2006–March, 2007, April, 2007–March, 2008, April, 2008–March, 2009, and the POI.



**Submission of information**

18. The exporters and importers known to be concerned and domestic industry are being informed separately to enable them to file all information relevant in the form and manner prescribed. Any other party interested to participate in the present investigation may write to:

**The Designated Authority**

**(Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties)**

**Government of India  
Ministry of Commerce & Industry  
Department of Commerce  
Udyog Bhavan, New Delhi-110011.**

**Time limit**

19. Any information relating to this investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the above address not later than 40 days from the date of publication of this notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record their findings on the basis of the facts available on record in accordance with the Rules supra.

**INSPECTION OF PUBLIC FILE**

20. In terms of rule 6(7) any interested party may inspect the public file containing non-confidential versions of the evidence submitted by other interested parties.

21. All interested parties shall provide a confidential and non-confidential summary in terms of Rule 7 (2), for the confidential information provided as per Rule 7 (1) of the Rules supra.

22. In case any interested party refuses access to and otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Governments as deemed fit.

**P. K. CHAUDHARY, Designated Authority**

3287 ED/10-3